हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

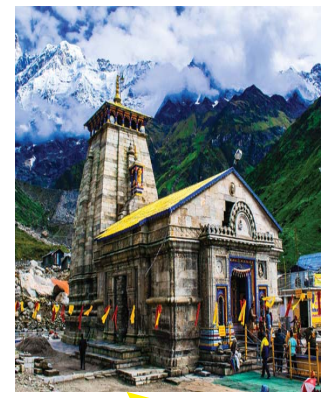

वर्ष:4 अंक:346 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, शनिवार, 20 दिसंबर 2025

अग्निवीर प्रशिक्षण की हकीकत पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सीधी नजर

देहरादून में अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण, युवाओं से संवाद कर बढ़ाया आत्मविश्वास

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा खेल विभाग द्वारा प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय, रायपुर (देहरादून) में संचालित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में वे प्रत्येक जिले के भ्रमण के दौरान वहां संचालित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे, ताकि प्रदेशभर में युवाओं को एक समान, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधे संवाद किया और उनके प्रशिक्षण अनुभव, दैनिक दिनचर्या, अनुशासन, शारीरिक अभ्यास तथा सामने आ रही चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने युवाओं से यह भी पूछा कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें किन सुविधाओं की और आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध दौड़ अभ्यास, शारीरिक प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों, अनुशासनात्मक अभ्यास और अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण से जुड़ी सभी सुविधाएं उच्च

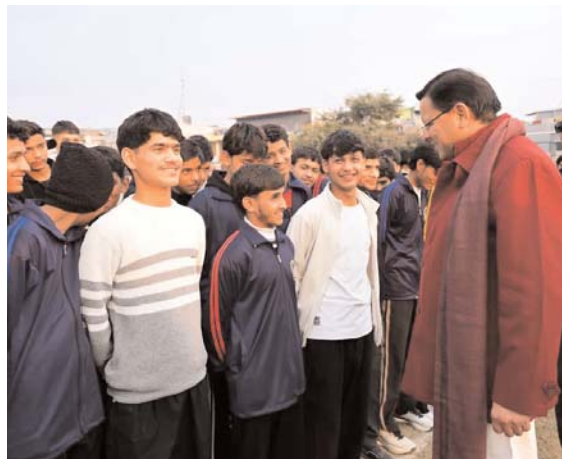

गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों और युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है, ताकि उत्तराखंड के अधिक से अधिक युवा पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ देश की सेवा के लिए चयनित हो सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं का मार्गदर्शन करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

युवाओं का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वयं भी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित खेल गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने युवाओं के साथ खेलते हुए उन्हें अनुशासन, परिश्रम, टीम भावना और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री की इस सहभागिता से प्रशिक्षणार्थी युवाओं में विशेष उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय-समय पर अपडेट किया जाए और विशेषज्ञ एवं अनुभवी प्रशिक्षकों की सहायता से युवाओं को शारीरिक के साथ-साथ मानसिक रूप से भी सशक्त बनाया जाए, ताकि वे अग्निवीर भर्ती की कठिन परीक्षा और प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निवीर योजना देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के युवा इस योजना के माध्यम से न केवल देश सेवा करें, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनें। युवाओं को हर संभव सुविधा और मार्गदर्शन देना हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा का अवसर मिल रहा है। यह योजना युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करती है। कम आयु में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा देश की सुरक्षा में योगदान देने के साथ-साथ जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी कौशल भी अर्जित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर प्रशिक्षण युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी सशक्त करता है। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासित दिनचर्या और टीम भावना से युवाओं में निर्णय क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बनती है।

उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर योजना से प्रशिक्षित युवा सेवा अवधि के पश्चात रोजगार और स्वरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में भी सक्षम बनते हैं। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान अर्जित अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व और तकनीकी दक्षता जैसे गुण उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उत्तराखंड के अधिक से अधिक युवा अग्निवीर योजना का लाभ उठा सकें। इसके लिए प्रदेशभर में निःशुल्क प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन, अनुभवी प्रशिक्षक और बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है।

निरीक्षण के दौरान विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, अपर सचिव डॉ. आशीष चौहान सहित खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा प्रांतीय रक्षक दल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का मार्ग दिखाया: प्रधानमंत्री

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के साथ शुक्रवार को परंपरागत चिकित्सा पर आयोजित दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) के वैश्विक सम्मेलन का समापन हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में तीन दिनों तक चले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर से आए पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने गहन और सार्थक विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए डब्लयूएचओ, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और सम्मेलन में शामिल सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में पहले वैश्विक सम्मेलन के दौरान दुनिया ने भारत पर भरोसा जताते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी।

श्री मोदी ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का मार्ग दिखाया है। उन्होंने बताया कि भारत के प्रयासों और 175 से अधिक देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। आज योग दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच चुका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योग के प्रचार-प्रसार में योगदान देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किये।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि आज दिल्ली में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व (साउथ-ईस्ट) क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने इसे भारत की ओर से दुनिया को दिया गया एक विनम्र उपहार बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय शोध, नियम निर्धारण और क्षमता निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

पूर्व सीएम व सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन पर सेवा और आस्था का संगम

नवजातों को दिया आशीर्वाद, मां गंगा की पूजा कर की देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना

पथ प्रवाह, हरिद्वार

पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सेवा, संवेदना और आस्था का अनुकरणीय संदेश दिया। इस अवसर पर वे हरिद्वार स्थित महिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जच्चा-बच्चा वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं को गर्म टोपी तथा प्रसूताओं को हल्दी वाला पौष्टिक दूध और आयुर्वेदिक च्यवनप्राश वितरित किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ईश्वर से नवजात शिशुओं के स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया।

अस्पताल में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अस्पताल परिसर में केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया। इसके उपरांत वे हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके स्नेही कार्यकर्ताओं ने अत्यंत स्नेह और आत्मीयता के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके लिए वे सभी के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र बेहद उपयोगी रहा, जिसकी प्रोडक्टिविटी 111 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि संसद देर रात दो-दो बजे तक चली और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत सरकार द्वारा लिए गए बड़े और दूरदर्शी निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े जो फैसले किए गए हैं, वे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। प्रदूषण से पूरी दुनिया त्रस्त है और भारत सरकार अब शुद्ध ऊर्जा की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 का भारत पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया को बड़ी राहत देगा।

हरिद्वार के विकास कार्यों पर बोलते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनता के लिए अनेक परियोजनाएं तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। ऑल वेदर रोड, बाईपास रोड, रिंग रोड और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को जोड़ा जा रहा है। साथ ही हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर देश-दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नई पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बनारस देखा है, वे कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में हरिद्वार एक अनोखा और भव्य शहर के रूप में उभरेगा।

इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर सुशील चौहान, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभिनव चौहान, जिला महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, भाजपा नेता उज्ज्वल पंडित, डॉ. विशाल गर्ग, मंडल अध्यक्ष वरुण वशिष्ठ, मोहित चौहान, तरुण चौहान, डॉ. संध्या शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे।

कुंभ मेले के कार्य नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी होंगे शामिल, ग्रीन घाट बनाने का बनाया प्रस्ताव

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन लगातार कार्ययोजना बनाकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसीक्रम में कुछ कार्यों के प्रस्ताव नमामि गंगे मिशन में शामिल कराए जाने के लिए सीसीआर में कुंभमेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बैठक की गई।

बैठक में डायरेक्टर शहरी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दिल्ली धीरज जोशी, परियोजना निदेशक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तराखंड विशाल मिश्रा, डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध, मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार सहित संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कुंभ मेले की व्यवस्थाओ के लिए एवं ग्रीन घाट बनाए जाने / घाटों के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों के प्रस्ताव का पीपीटी के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया गया। इस

अवसर पर मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि कुंभ मेले के लिए तीन घाटों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव के साथ ग्रीन घाट बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा पेयजल निगम द्वारा एसटीपी प्लांट का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है इसके साथ ही म्यूजियम भी बनाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए गए है,जिनकी गहन समीक्षा की गई।

बैठक में डायरेक्टर शहरी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दिल्ली धीरज जोशी ने कहा कि कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं के लिए जो भी प्रस्ताव तैयार किए गए है उन प्रस्तावों को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ,नई दिल्ली के समक्ष रखा जाएगा। बैठक में अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती,एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह,एडिशनल एसपी विपिन कुमार,एनआईयूए राहुल सचदेवा, संचार विशेषज्ञ पूरन कापड़ी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर सत्यदेव आर्य सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। बैठक के बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की टीम द्वारा सीसीआर से वीआईपी घाट तक विभिन्न घाटों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया गया।

एक नजर

रानीपुर से 13 वर्षीय छात्रा लापता, पड़ोसी पर आरोप

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया कि बीते 16 दिसंबर की सुबह उनकी बेटी रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की गई, लेकिन छात्रा का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया है। घटना के बाद से परिवार गहरे सदमे और चिंता में है। परिजनों ने पुलिस से छात्रा की सकुशल बरामदगी के साथ-साथ आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग छात्रा को सकुशल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

शहर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को मुजफ्फरनगर से दबोचा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली नगर पुलिस ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में वांछित आरोपी शिवम सैनी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी पर युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में गाली-गलौज करने का आरोप था। पुलिस के अनुसार, 10 दिसंबर को वादिया अंजली पुत्री श्यामलाल, निवासी विष्णुलोक कॉलोनी, बीएचईएल रानीपुर ने कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिवम सैनी पुत्र वेदप्रकाश उर्फ लोकेश, निवासी ग्राम कवाल, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर (उप्र) ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद गाली-गलौज की। शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए सतर्कता एवं सुरागरसी-पतारसी के आधार पर गुरुवार को आरोपी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली नगर पुलिस के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी में वरिष्ठ उप निरीक्षक नंदकिशोर ग्वाड़ी, महिला उप निरीक्षक अनिता शर्मा, हेड कांस्टेबल सतीश नौटियाल और कांस्टेबल सुनील चौहान सहित पुलिस की पूरी टीम शामिल रही।

सिंचाई विभाग ने सरकारी भूमि से अभियान चलाकर हटाये अतिक्रमण और अवैध कब्जे

पथ प्रवाह, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने शुक्रवार को बहादराबाद में सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया। इस दौरान करीब 30 अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया जबकि 40 से अधिक दुकानों के बाहर किये गए अतिक्रमण को तोड़ा गया। अभियान के दौरान पृथ्वी राज चौहान तिराहे के पास सिचाई विभाग की छोटी नहर पटरी पर वर्षो से झुग्गीझोपड़ी डाल कर रहने वाली खानाबदोशों की झोपड़ियो को हटा दिया गया। एक सप्ताह पूर्व भी यहां अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी लेकिन तब विरोध के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा था। तब अधिकारियों ने दो दिन का समय देते हुए स्वंय ही अतिक्रमण हटाने के लिए चे?तावनी दी थी। इससे पहले नोटिस दिये गए थे। शुक्रवार केा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी पुलिस बल के साथ छोटी नहर पटरी से झुग्गी झोपड़ियो, ठेली,

अस्थाई दुकानों को हटाने के लिये पहुंची। इस दौरान सभी अतिक्रमण सख्ती के साथ हटा दिये गए। टीम के साथ मौजूद पुलिस फोर्स के चलते किसी ने विरोध भी नहीं किया। कुछ स्थानों पर लोगों ने स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटाए। पुलिस चौकी के पास काली मंदिर तिराहे के बीच हाल ही में टिन शेड डाल कर बनाई दुकानों को हटाने पहुंची टीम की कार्रवाई से पहले ही यहाँ की दुकानों को भी विभाग ने हटा दिया। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम में एसडीएम जितेंद्र कुमार, एसडीओ भारत भूषण, डीआरओ मुनेश सैनी, अमीम मनोज कुमार, दिवेश कुमार, जिलेदार मनीष, जेई अश्वनी एवं अतुल कुमार मौजूद रहे। सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण का कहना है कि सिंचाई विभाग अपनी अधिकार क्षेत्र की समस्त भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है।

एचआरडीए का सुशासन कैंप बना जनता के लिए राहत का केंद्र, 54 मानचित्रों का निस्तारण

पथ प्रवाह, हरिद्वार/रुड़की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को शाखा कार्यालय रुड़की के सभागार में सुशासन कैंप का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी दो सुशासन कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

कैंप में बड़ी संख्या में नागरिक एवं आवेदक अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु पहुँचे। इस अवसर पर सचिव एचआरडीए मनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव दीपक रामचंद्र सेठ, अधीक्षण अभियंता राजन सिंह, सहायक अभियंता वर्षा, सहायक अभियंता प्रशांत सेमवाल, टेक्निकल कंसल्टेंट गोविंद, अवर अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कैंप की अध्यक्षता करते हुए एचआरडीए की उपाध्यक्ष सोनिका ने प्रकरणों

की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदक की समस्या का निस्तारण त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक ढंग से किया जाए, ताकि आमजन को सुशासन का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यही सुशासन कैंप का उद्देश्य है। कैंप के दौरान कुल 54 मानचित्रों का निस्तारण किया गया, जिनमें 33 मानचित्र स्वीकृत तथा 21 मानचित्र निर्गत किए गए। त्वरित समाधान और सहज प्रक्रिया से आवेदकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लाभार्थियों ने धामी सरकार की इस पहल और एचआरडीए की कार्यप्रणाली की मुक्तकंठ से सराहना की। एचआरडीए ने जानकारी दी कि अगला सुशासन कैंप आगामी 22 दिसम्बर को तहसील भगवानपुर के सभागार में आयोजित किया जाएगा। प्राधिकरण ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे सुशासन कैंप में पहुँचकर अपने निर्माण मानचित्र, शुल्क निस्तारण, तकनीकी समाधान एवं अन्य विकास संबंधी मामलों का त्वरित समाधान प्राप्त करें।

तीर्थ नगरी दिखने लगी स्वच्छ और सुंदर, गंदगी करने वालों के काटे जा रहे चालान

पथ प्रवाह, हरिद्वार। तीर्थनगरी हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर, क्लीन जनपद बनाने के लिए सफाई अभियान का सफलता पूर्वक एक माह पूर्ण कर लिया है। शुक्रवार से अभियान ने दूसरे माह में प्रवेश कर लिया। सफाई अभियान नगर क्षेत्र से लेकर गांव कस्बों में और सड़क मार्गों पर चलाया जा रहा है। जिसका असर धरातल पर दिख रहा है। गंदगी फैलाने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। पूरे अभियान की जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं निगरानी कर रहे हैं।

अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचआई अतुल शर्मा ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा पंतद्वीप पार्किंग क्षेत्रांतर्गत सड़क किनारे साफ सफाई एवं झाड़ी कटान का कार्य किया गया है इसके साथ ही नारसन क्षेत्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए गड्ढों को गड्ढा मुक्त कराते हुए पेच वर्क का कार्य किया जा रहा है।

अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी विपुल सैनी ने अवगत कराया है कि कोर कॉलेज के पास ओल्ड एन एच 58 से रुड़की की ओर सड़क किनारे की झाड़ी कटान एवं साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है इसके साथ ही सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है एवं घने कोहरे के कारण कोई सड़क दुर्घटना गठित न हो इसके लिए सफेद पट्टी लगाए जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

अधिशासी अभियंता लोनिवि दीपक कुमार ने अवगत कराया है कि रोशनाबाद बिहारीगढ़ में सड़क किनारे साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा हैं। अपर परियोजना निर्देशक नलिनीत घिल्डियाल ने अवगत कराया है कि महिला समूह प्रकाशमय द्वारा नौकरग्रांट एवं सपना

समूह द्वारा लिबरहेडी, गोपालपुर ब्लॉक नारसन में भी सफाई अभियान का कार्य किया गया।

विकास खंड़ों में भी प्रतिदिन चल रहा अभियान

खंड विकास अधिकारी खानपुर राजेंद्र जोशी ने अवगत कराया कि खानपुर क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई अभियान चलाया गया साथ ही कूड़ा उठाया गया। खंड विकास अधिकारी नारसन सुभाष सैनी ने अवगत कराया है कि पंचायत भवन ग्राम पंचायत नसीरपुर,अफजलपुर क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई अभियान चलाया गया। ईओ झबरेडा हर्ष रावत ने अवगत कराया है कि नगर पंचायत झबरेडा के मुख्य मार्गो एवं सभी वार्डो में निरंतर सफाई का कार्य किया जा रहा है।

खंड विकास अधिकारी बहादराबाद मानस मित्तल ने अवगत कराया है कि आत्मालपुर बोंग्ला क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई अभियान चलाया गया। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राकेश खंडूरी ने अवगत कराया है कि जिला पंचायत द्वारा भी निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है आज बुग्गावाला ग्रामीण बाजार भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई एवं पालीथीन प्लास्टिक अवशिष्ट को एकत्रित किया गया इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले पर एवं सफाई न करने वाले दुकानदारों पर चालान की कार्यवाही की गई।

देशी विदेशी मदिरा की दुकानों पर अभियान

जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बिंजोला ने अवगत कराया है कि देशी विदेशी मदिरा की दुकानों पर साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अधिशासी अभियंता जल निगम राजेश गुप्ता ने अवगत कराया है कि जनपद में संचालित पेयजल योजनाओं के परिसर में झाड़ी कटान एवं साफ सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है,आज नसीरपुर,रतनपुर पेयजल योजनाओं के कैंपस में सफाई अभियान चलाया गया।

धार्मिक स्थलों और परिसरों में सफाई

अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी ने अवगत कराया है कि आज चंडी देवी पैदल मार्ग पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। तीर्थ नगरी जनपद हरिद्वार को स्वच्छ,सुंदर जनपद बनाने के लिए चलता जा रहे सफाई अभियान में मुख्यमंत्री ने सफाई अभियान में सभी से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने सभी जनपद वासियों ,धार्मिक संस्थाओं,साधु समाज,व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं से भी इस अभियान में अपनी भागीदारी करने की अपील की है।

सिटी हॉस्पिटल में करोड़ों की कथित अनियमितताओं का खुलासा, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने दर्ज कराया मुकदमा

पथ प्रवाह, हरिद्वार

नगर के जाने-माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. सुमंतु विरमानी ने सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली ज्वालापुर में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना, आपराधिक विश्वासघात, अवैध निर्माण, धन के दुरुपयोग तथा महंगे सर्जिकल उपकरणों की चोरी जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डॉ. विरमानी ने पुलिस को बताया कि वे वर्ष 2000 से मैसर्स हरिद्वार लैंड एंड फाइनेंसर्स (सिटी हॉस्पिटल) में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ विधिवत साझेदार हैं। वे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और जून 2025 से सिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान उनके द्वारा भर्ती किए गए मरीजों के सभी ऑपरेशन सिटी हॉस्पिटल में ही किए जाते रहे।

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि फर्म के मुख्य प्रबंधक शिव कुमार कपूर ने अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके साथ छल और धोखाधड़ी की। आरोप है कि अस्पताल से जुड़े नक्शे, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित कई विभागीय दस्तावेज फर्जी और कूटरचित तैयार किए गए। इन्हीं कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अस्पताल परिसर में अतिरिक्त अवैध निर्माण कर नए चिकित्सा उपकरण लगाए गए और रेडियोलॉजी व स्कैनिंग जैसी सेवाओं से अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।

डॉ. विरमानी ने यह भी आरोप लगाया कि सिटी हॉस्पिटल, सुपर कॉम्प्लेक्स, हरिद्वार स्थित ऑपरेशन थिएटर परिसर से उनके निजी स्वामित्व वाले महंगे सर्जिकल उपकरण, मशीनरी और इम्प्लांट चोरी कर लिए गए। इन उपकरणों की अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपये बताई गई है। आरोप है कि यह सामग्री शिव कुमार कपूर और उनके सहयोगियों द्वारा आपसी मिलीभगत से अस्पताल परिसर से हटाकर किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दी गई।

तहरीर में यह भी उल्लेख है कि ऑर्थोपेडिक मरीजों को गुमराह करने के उद्देश्य से अस्पताल परिसर में बैनर लगाकर उन्हें अन्य सर्जनों की ओर मोड़ा गया, जिससे जानबूझकर उनकी सेवाओं को बाधित किया गया और लगातार आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। जब डॉ. विरमानी ने इस संबंध में सवाल किए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, गालियां दी गईं और सिटी हॉस्पिटल में प्रवेश न करने व जान से मारने की धमकी तक दी गई। इसके अलावा आरोप है कि बिना साझेदार की जानकारी और सहमति के फर्म की संपत्ति के कागजात गिरवी रखकर बैंक से ऋण लिया गया। साथ ही, अस्पताल से सटे निजी भवन को शिव कुमार कपूर और उनकी पत्नी के नाम से अस्पताल को किराये पर देकर उसका किराया स्वयं लिया गया, जिससे साझेदारी फर्म को आर्थिक नुकसान पहुंचा। वर्ष 2021-22 में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिटी हॉस्पिटल का पीएम-जेएवाई आयुष्मान भारत योजना व अन्य बीमा कंपनियों में एम्पैनलमेंट कराकर धन लाभ अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है।

डॉ. विरमानी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड आवास विकास प्राधिकरण द्वारा 01 अगस्त 2025 को अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश की कार्यवाही की मांग की गई, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई और 5 प्रतिशत साझेदार होने के नाते उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी कुंदन सिंह राणा का कहना है कि डॉ. सुमंतु विरमानी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले से जुड़े सभी बिंदुओं की गहन जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार को नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में बड़ी उपलब्धि, मिला राज्य स्तरीय सम्मान

पथ प्रवाह, हरिद्वार

नीति आयोग के संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जनपद हरिद्वार ने राज्य स्तर पर बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल निर्देशन एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सशक्त नेतृत्व में संचालित संपूर्णता अभियान कार्यक्रम के लिए जनपद हरिद्वार को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन/मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए हरिद्वार जनपद की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान

कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद हरिद्वार की पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि समन्वय, नवाचार और समर्पण से ही विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नीति आयोग से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मवीर यादव, अपर जिला सांख्यकीय अधिकारी सुभाष सिंह शाक्य, खंड विकास अधिकारी बहादराबाद मानस मित्तल, चिकित्साधिकारी डॉ. कोमल, खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, निम्मी राणा, अवतारी सती, राजकुमार, जयवीर कौशल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।

हरिद्वार को स्वच्छ-सुंदर बनाने की मुहिम तेज, उद्योगों के सहयोग से चला व्यापक सफाई अभियान

पथ प्रवाह, हरिद्वार

हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर एवं क्लीन जनपद के रूप में विकसित करने की दिशा में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित निरंतर सक्रिय एवं प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा इस अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए सिडकुल सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार देर सायं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिडकुल एवं अन्य कंपनियों के अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सफाई कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किर्बी चौक से पिटकुल कार्यालय मार्ग, राजा बिस्कुट फैक्ट्री क्षेत्र, महेंद्रा फैक्ट्री परिसर तथा कांवड़ पटरी मार्ग (सिंह द्वार से ज्वालापुर की ओर) पर चल रहे सफाई कार्यों

को देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य केवल औपचारिक न होकर गुणवत्ता एवं निरंतरता के साथ किया जाए, ताकि शहर की छवि स्वच्छ और सुंदर बने।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिडकुल के आरएम कमल किशोर कफल्टिया सहित अन्य कंपनियों के अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि इस अभियान में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें तथा आमजन को भी स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन, उद्योग और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही हरिद्वार को स्वच्छ एवं आदर्श जनपद बनाया जा सकता है।

सिडकुल के आरएम कमल किशोर कफल्टिया ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि सिडकुल क्षेत्र में नियमित रूप से साफ-सफाई कराई जा रही है तथा सफाई कार्यों में रोड स्वीप वाहन को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे कार्यों में तेजी और प्रभावशीलता आएगी। साथ ही इस अभियान में अन्य औद्योगिक इकाइयों का भी सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है।

एकम्स कंपनी के जीएम के.डी. शर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा कांवड़ पटरी मार्ग की लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई में झाड़ी कटान, सड़क की साफ-सफाई एवं सड़क किनारे क्षेत्रों का समलीकरण कार्य कराया जा रहा है। वहीं नील मेटल कंपनी द्वारा भी लगभग 300 मीटर कांवड़ पटरी मार्ग पर झाड़ी कटान एवं सफाई कार्य किया जा रहा है।

महेंद्रा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी अजय वर्मा ने आश्वस्त किया कि उनकी कंपनी भी इस स्वच्छता अभियान में पूर्ण सहयोग दे रही है और अपने क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई कराई जा रही है। इसी क्रम में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के एचआर पंकज शर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड फैक्ट्री से राजा बिस्कुट फैक्ट्री तक सफाई कार्य में निरंतर सहयोग किया जा रहा है।

इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी एच.पी. नौटियाल, सहायक वास्तुविद अभिनव रावत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी को स्वच्छता के इस अभियान को निरंतर और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें डालने का आरोप, देवबंद के युवक पर मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक पीड़ित युवती ने देवबंद निवासी युवक पर शादी के लिए दबाव बनाने, जान से मारने की धमकी देने तथा सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील व न्यूड तस्वीरें डालकर सामाजिक छवि धूमिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सहारनपुर जनपद के देवबंद निवासी अक्षय सिंह पुत्र कुलदीप सिंह के मोहल्ले में उसकी रिश्तेदारी है। इसी दौरान दोनों की जान-पहचान हुई और बाद में फोन पर बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि आरोपी ने इस बातचीत का गलत लाभ उठाते हुए युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार, जब उसके परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, तो आरोपी ने आपत्ति जताते हुए उसे धमकाया और कहा कि वह उसके अलावा किसी अन्य से शादी नहीं कर सकती। युवती का आरोप है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने दूसरी जगह शादी की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहीं नहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी की बात मानने से इनकार किया तो आरोपी ने उसकी अश्लील एवं न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डाल दीं, जिससे उसकी सामाजिक छवि को भारी नुकसान पहुंचा। पीड़िता का कहना है कि जब इस संबंध में आरोपी और उसके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने भी आरोपी का ही समर्थन किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर उसे और उसके परिवार को बदनाम कर रहा है, जिससे वह और उसके परिजन भय और मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने नगर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से कराएं निराकरण: मकवाना

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण कराया जाए। वह शुक्रवार को नगर निगम सभागार रुड़की में सफाई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें हर हाल में उपलब्ध हो इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता एवं लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छकारों हेतु नमस्ते योजना चल रही है जिसमें सीवरेज सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा कवर, स्वास्थ्य बीमा, मृत्यु और दुर्घटना बीमा की शुरू करने के आदेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि बस्तियों में भी विकास कार्य हो साथ ही सफाईकर्मियों को वर्दी, सुरक्षा सब चीजे उपलब्ध करायी जाये साथ ही सभी कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ, मुख्य नगर आयुक्त रुड़की राकेश चंद्र तिवारी, एसएनए रुड़की अमरजीत कौर, एसीएमओ डॉ अनिल वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया, प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला, उत्तराखंड निकाय कर्मचारी सयुक्त मोर्चा के नेता राजेंद्र श्रमिक सहित सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।

संपादकीय

जीरो टॉलरेंस बनाम जमीनी हकीकतः खंड शिक्षा अधिकारी का दुस्साहस और सरकार की साख का सवाल

उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान के रूप में प्रस्तुत करती रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते वर्षों में कई बड़े और छोटे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई, अनेक अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए और यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब इसी दौर में एक खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुलिस महकमे से जुड़े सरकारी स्कूल से रिश्वत मांगने और दबाव बनाने का मामला सामने आता है, तो यह पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सरकारी स्कूल, वह भी पुलिस विभाग से जुड़ा, किसी निजी संस्था की तरह नहीं है जिसे डराकर या दबाव में लेकर अवैध वसूली की जा सके। यह राज्य की ही एक इकाई है, जो कानून और व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे संस्थान से रिश्वत मांगना न केवल नैतिक पतन का परिचायक है, बल्कि यह सीधे तौर पर सरकार की नीतियों, निर्देशों और मुख्यमंत्री की सख्ती को खुली चुनौती देने जैसा है। खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल राठौर द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप यदि सही पाया जाता है, तो इसे सामान्य प्रशासनिक चूक कहना वास्तविकता से मुंह मोड़ना होगा। यह एक स्पष्ट दुस्साहस है।

सरकार यह दावा करती रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई 'परत दर परत' की जा रही है। कई मामलों में विजिलेंस, पुलिस और प्रशासन ने तत्परता दिखाई भी है। लेकिन ऐसे मामलों का सामने आना यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं जीरो टॉलरेंस का भय निचले स्तर तक प्रभावी नहीं हो पाया है। यदि वास्तव में मुख्यमंत्री की सख्ती का असर जमीन पर महसूस हो रहा होता, तो कोई खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत मांगने का साहस ही नहीं करता। और यदि साहस किया है, तो यह दर्शाता है कि कुछ अधिकारी अब भी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं।

यह मामला केवल एक अधिकारी विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे शिक्षा विभाग और प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है। शिक्षा विभाग, जिसे समाज के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यदि वहीं भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होंगी तो इसका सीधा असर व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। पुलिस महकमे से रिश्वत मांगना इस बात का भी संकेत है कि आरोपी अधिकारी को न तो कानून का डर है और न ही कार्रवाई का।

जनता सरकार से यह अपेक्षा करती है कि वह जीरो टॉलरेंस की नीति को चरितार्थ करें। सरकार अपनी अब तक की उपलब्धियों की दुहाई देकर ऐसे मामलों को हल्के में न ले। बल्कि इस प्रकरण को एक कसौटी मानते हुए त्वरित, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई करे। केवल निलंबन या विभागीय जांच से आगे बढ़कर यदि दोष सिद्ध होता है तो सख्त दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि एक स्पष्ट संदेश जाए कि जीरो टॉलरेंस कोई नारा नहीं, बल्कि व्यवहारिक नीति है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख और सरकार की विश्वसनीयता इसी में निहित है कि ऐसे दुस्साहस पर कितना निर्णायक प्रहार होता है। यदि समय रहते कठोर कदम उठाए गए, तो यह न केवल भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले पस्त करेगा, बल्कि आम जनता और ईमानदार कर्मचारियों का भरोसा भी मजबूत करेगा। वरना जीरो टॉलरेंस का दावा केवल भाषणों और फाइलों तक सिमट कर रह जाएगा, और यही किसी भी सुशासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

विकसित देशों के सम्पन्न नागरिक भारत में बसने के बारे में कर रहे हैं गम्भीर विचार

प्रहलाद सबनानी

वैश्विक पटल पर अचानक परिस्थितियां बहुत तेजी के साथ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक कुशल युवा भारतीय अपना सपना साकार करने के उद्देश्य से अमेरिका में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए जाते रहे हैं। परंतु, अब कुछ अलग प्रकार का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका सहित अन्य कई विकसित देशों में रहन सहन (जीवन निर्वहन) के खर्चे असहनीय स्तर पर पहुंच गए हैं क्योंकि मुद्रा स्फीति की समस्या इन देशों में लम्बे समय से चल रही है, और, इन देशों द्वारा इस संदर्भ में अथक प्रयास करने के बावजूद, इसका हल नहीं निकल पा रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंच गई हैं। विकसित देशों में किसी भी नागरिक को स्वास्थय इंशोरेंस की सुविधा यदि उपलब्ध नहीं हैं तो उसके लिए इलाज करना असम्भव सा ही है। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत इन देशों में इतनी बढ़ चुकी है कि आम नागरिक के लिए यहां अपना इलाज करना सम्भव ही नहीं हैं। अमेरिका से तो युवाओं के साथ साथ सेवानिवृत्त नागरिक भी अब भारत में बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क, टेकसास, वाशिंगटन, लासअंजेल्स, सिलिकन वेल्ली, आदि शहरों से इंजीनियर, सृजक (क्रीएटर), युवा उद्यम, बुजुर्ग नागरिक, आदि निकलकर भारत के मुंबई, पुणे, गोवा, हैदराबाद, बैंगलोर, केरल, पोंडिचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि शहरों/राज्यों में आकर भारत में बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

भारत की तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत में तुलनात्मक रूप से सस्ती दरों पर विभिन्न उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता, अति सस्ती दरों पर सेवा भावना के साथ उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं भारत की महान संस्कृति के साथ साथ साकार अवसर अमेरिका सहित विकसित देशों के नागरिकों को भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज भारत का फलता फूलता तकनीकी उद्योग उच्च स्तर की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है जो किसी भी तरह विकसित देशों में उपलब्ध कराई जा जा रही तकनीकी सुविधाओं से कम नहीं हैं। भारत में नागरिकों को मानसिक शांति उपलब्ध है क्योंकि भारतीय नागरिक, सनातन संस्कृति का अनुपालन करते हैं। जबकि विकसित देशों के नागरिकों में मानसिक शांति का पूर्णतः अभाव है। विकसित देशों के नागरिक पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते हैं जिसके चलते संयुक्त परिवारों का पूर्णतः अभाव है। इन देशों में पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करते हुए परिवारों में बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही वे अपना अलग घर बसा लेते हैं और माता पिता अकेले रह जाते हैं। जिससे, माता पिता अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और इनकी देखभाल के लिए सरकार को व्यवस्था करनी होती है। इसके ठीक विपरीत भारतीय संस्कृति नागरिकों को आपस में जोड़ती है एवं संयुक्त परिवार भारतीय समाज की विशेषता है। बुजुर्ग नागरिकों को अपने संयुक्त परिवार में ही रहना होता है। अतः भारत में बुजुर्गों की देखभाल के लिए सरकार को अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी होती है।

हाल ही के वर्षों में अमेरिकी नागरिकों द्वारा भारत के लिए वीजा प्राप्त करने वालों की संख्या वर्ष 2021 के बाद से दुगुनी हो गई है। अमेरिकी नागरिक अब भारत में शांति की तलाश में आ रहे हैं। अमेरिका सहित विकसित देशों में अधिकतम नागरिकों को मानसिक बीमारियों ने घेर रखा है। इन मानसिक बीमारियों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से कई विदेशी नागरिक तो भारत के हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों के हिमालय क्षेत्र में बस्ते जा रहे हैं। उन्हें वहां पर आध्यात्म का सुख प्राप्त हो रहा है। भारत की तेजी से बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था से भी अमेरिका का पढ़ा लिखा वर्ग आकर्षित हो रहा है, क्योंकि उन्हें अमेरिका जैसी ही उच्चस्तरीय सुविधाएं भारत में भी उपलब्ध हो रही हैं। भारत का स्टार्टअप इको सिस्टम भी भारत में नित नए नवाचार उपलब्ध करा रहा है इससे अमेरिका में पूर्व से ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भी भारत में रोजगार के नए अवसर दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही, भारत में प्रतिभावान इंजीनीयरों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है जिससे अमेरिका की कई कम्पनियां अब अपने तकनीकी कार्य को भारत में स्थानांतरित कर रही हैं। कई अमेरिकी कम्पनियां अब यह महसूस करने लगी हैं कि भारत में कम खर्चों में अधिक उत्पादकता मिल सकती है, क्योंकि भारत में उत्पादों की लागतें एवं कार्यबल की लागतें बहुत कम हैं, जिससे तुलनात्मक रूप से इन कम्पनियों की लाभप्रदता में सुधार दिखाई दे रहा है। अमेरिका में उत्पादों की लागतें बहुत ऊंचें स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जो कम्पनियों की लाभप्रदता को विपरीत रूप से प्रभावित कर रही हैं। और फिर, भारतीय महानगरों में अमेरिकी महानगरों की तुलना में बेहतर एवं टक्कर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी उपलब्ध है जिससे उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली विश्व की लगभग समस्त बड़ी कंपनियां अब भारत में अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही हैं। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में सस्ती उत्पादन लागत पर उत्पादों का निर्माण कर भारत में ही इन उत्पादों को बेच सकती हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही इन उत्पादों के लिए विशाल बाजार उपलब्ध है। अन्य कई कम्पनियां तो भारत में स्थापित विनिर्माण इकाईयों में उत्पादों का निर्माण कर अन्य देशों को निर्यात भी करने लगी हैं।

भारत में आधुनिकतम तकनीकी उपलब्ध है, रहन सहन की लागतें बहुत कम हैं, युवा एवं प्रतिभावान कार्यबल सस्ती दरों पर उपलब्ध है, भारत में मुद्रा स्फीति की दर सबसे कम है, उत्पादों का बड़ा बाजार उपलब्ध है, इन उपलब्धियों की चलते अब विदेशी निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अमेरिका सहित विकसित देशों में आज मुद्रा स्फीति की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है एवं इसका हल ये देश निकाल नहीं पा रहे हैं इससे इन देशों में पेंशन पाने वाले नागरिक इन देशों में रहन सहन की उच्च लागत को वहन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भारत में इन देशों के नागरिकों का गुजारा बहुत आसानी से हो सकता है। साथ ही, भारत में हाल ही के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि में अकल्पनीय सुधार हुआ है। भारत में ही अब विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं तुलनात्मक रूप से बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। अन्य देशों की तुलना में केवल 25/30 प्रतिशत खर्च पर भारत में अत्याधुनिक तकनीकी आधारित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतः आज न केवल विकसित देशों बल्कि अरब देशों से भी नागरिक भारत में अपना इलाज कराने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आने लगे हैं।

भारतीय संस्कृति भी विदेशी नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। मन की शांति तो भारत के आध्यात्म में अंतर्निहित है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना, 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' एवं 'सर्वे भवंतु सुखिनः' जैसी भावना तो केवल और केवल भारत में ही पाई जाती है। भारत में योगा एवं आयुर्वेदिक जैसी सुविधाएं भी स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में सहयोग करते हुए दिखाई दे रही हैं। पश्चिम के केवल 'मैं' के भाव से भी नागरिक अब ऊब चुके हैं एवं वहां पर छिन्न-भिन्न हुए सामाजिक ताने-बाने से भी बहुत परेशान हैं अतः वे आत्मिक सुख की तलाश में भारत के सामाजिक ताने बाने में रचना बसना चाह रहे हैं।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा संकट

निर्मल रानी

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में दुनिया की सबसे जटिल समझी जाने वाली चुनावी प्रक्रिया को अपनाने व इसे पूरा कराने को लेकर जिस केंद्रीय चुनाव आयोग की पीठ पूरी दुनिया थपथपाया करती थी व दुनिया के विभिन्न देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल व चुनाव विशेषज्ञ जिस भारतीय चुनाव संचालन को देखने व समझने के लिये अब भी भारत आते रहते हैं वही चुनाव व चुनाव आयोग इन दिनों विपक्षी दलों के अति गंभीर आरोपों से जूझ रहा है। चुनाव आयोग व इस तरह के कई अन्य केंद्रीय संस्थानों पर सत्ता का पक्षपात करने के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं। परन्तु वर्तमान चुनाव आयोग जिसतरह सत्ता को फ़ायदा पहुँचाने वाले नए नए चुनावी नियम बना रहा है,विपक्ष की प्रमाण सहित दी जाने वाली शिकयतों की अनसुनी कर रहा है,सत्ता द्वारा चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाने के बावजूद आँखें मूंदे बैठा रहता है,और अब एस आई आर के बहाने कथित तौर पर जहाँ करोड़ों फ़र्ज़ी मतों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है वहीँ संभावित रूप से विपक्ष की ओर जाने वाले मतों को चिन्हित कर उन्हें किसी न किसी बहाने से मतदाता सूची से काटने का काम किया जा रहा है। यानी स्पष्ट रूप से लोकततंत्र में लोक के मताधिकार पर डाका डाला जा रहा है। वैसे तो पूरा विपक्ष ही चुनाव आयोग को केवल संदेह नहीं बल्कि सत्ता से मिलकर संविधान के साथ विश्वासघात किये जाने की दृष्टि से देख रहा है। लोक सभा व राज्य सभा के सर्वोच्च सदनों में चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। परन्तु नेता विपक्ष राहुल गाँधी ने तो चुनाव आयोग द्वारा की और करायी जाने वाली धांधली पर तो बाक़ायदा शोध कर डाला है। और वे अपने इस चुनाव धांधली सम्बन्धी शोध परिणाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित करने से लेकर जनता जनार्दन के बीच सड़कों व गलियों तक पहुँच रहे हैं। इस संबंध वे अब तक 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के पूरे सबूत पेश कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे अगस्त-सितंबर 2025 के बीच बिहार में 16 दिनों की 1,300 किमी लंबी वोटर अधिकार यात्रा भी स्ट्रक्र के विरुद्ध निकाल चुके हैं। इसके अलावा 200 से अधिक सांसदों व विधायकों के साथ वे 11 अगस्त 2025 को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्यालय तक एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन रुपी पैदल मार्च भी कर चुके हैं। एक ओर तो राहुल चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा के अनुसार ही आयोग द्वारा बरती गयी अनियमितताओं संबंधी साक्ष्य पेश करते हैं तो दूसरी ओर चुनाव आयोग कभी इन आरोपों को बेबुनियाद बता कर अपना पल्ला झाड़ लेता है तो कभी उल्टे राहुल से ही शपथ-पत्र मांगने लगता है। परन्तु लगता है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने तो गोया चुनाव आयोग को पूरी तरह बेनक़ाब करने का संकल्प ही कर लिया है। गत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक विशाल रैली आयोजित की।

वोट चोर, गद्दी छोड़ के शीर्षक से किये गये इस आयोजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशभर से लाखों कार्यकर्ता जुटाये। इस रैली का भी मुख्य उद्देश्य हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हाल के विधानसभा चुनावों में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगाना था। इस विशाल रैली में भी कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा का संकल्प लिया।

अफ्रीका की धरती पर भारत का आत्मीय स्वागत, इथियोपिया में मोदी युग की नई साझेदारी

कांतिलाल मांडोत

अफ्रीका के हृदय कहे जाने वाले इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत-इथियोपिया के हजारों वर्ष पुराने संबंधों को नई ऊर्जा देने वाला ऐतिहासिक क्षण बन गया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अदीस अबाबा के बोले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, वहां आत्मीयता, सम्मान और अपनत्व का ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को स्पष्ट कर दिया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली स्वयं प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंचे और सबसे विशेष बात यह रही कि वे खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट से होटल तक लेकर गए। यह दृश्य केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि अफ्रीकी संस्कृति में मित्रता और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इथियोपिया की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली पारंपरिक कॉफी सेरेमनी के माध्यम से उनका अभिनंदन हुआ। यह रस्म इथियोपिया में सम्मान और अपनत्व का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। प्रवासी भारतीयों ने 'भारत माता की जय' और 'मोदी-मोदी' के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों, पारंपरिक नृत्यों और भारतीय तिरंगे के बीच पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस गर्मजोशी को महसूस करते हुए कहा कि इथियोपिया की धरती पर आकर उन्हें अपनेपन का अहसास हो रहा है।

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इथियोपिया की ओर से किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला सर्वोच्च अलंकरण है। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का गौरव बताया और कहा कि यह सम्मान भारत और इथियोपिया की साझा मित्रता, साझा मूल्यों और साझा भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अफ्रीका के साथ साझेदारी को अपने शर्तों पर नहीं, बल्कि अफ्रीका की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि सभ्यतागत साथी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत औपनिवेशिक शासन से जूझ रहा था, तब इथियोपिया भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। दोनों देशों ने कभी एक-दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाए और हमेशा शांति, संप्रभुता और समानता के सिद्धांतों का समर्थन किया।

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत-इथियोपिया संबंध अब केवल सहयोग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें रणनीतिक साझेदारी में बदला जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर भी दोनों नेताओं के विचार एक जैसे दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके समर्थन या औचित्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इथियोपिया की ओर से आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद भी दिया। व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और इथियोपिया के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इथियोपिया में भारत सबसे बड़ा निवेशक है और भारत, इथियोपिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने थानेदार को किया लाइन हाजिर, पुलिस महकमे में हड़कंप

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान थानेदार के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील दायित्वों में किसी भी स्तर की लापरवाही अक्षम्य है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विभिन्न बैठकों के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अचानक थाने पहुंचने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर व्यवस्थाओं की कमियां उजागर हुईं, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने की कार्यप्रणाली ही शासन-प्रशासन की कार्यसंस्कृति का प्रतिबिंब होती है।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थाने में आए शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल औपचारिकता न मानते हुए उत्तरदायित्व की भावना से दर्ज किया जाए और उनका त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री महिला हेल्प डेस्क पर भी पहुंचे और महिला फरियादियों से बातचीत कर उनकी शिकायतों की जानकारी ली। उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई को अनिवार्य बताते हुए किसी भी प्रकार की ढिलाई पर सख्त चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री ने एफआईआर रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर एवं उपस्थिति रजिस्टर का गहन निरीक्षण करते हुए लंबित मामलों, फॉलोअप और कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही थाने में स्थित हवालात में गंदगी और अव्यवस्था पर गहरी नाराज़गी जताते हुए तत्काल साफ-सफाई और मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वाहन जांच, वेरिफिकेशन ड्राइव और अपराध नियंत्रण अभियानों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक अव्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया और विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून मौके पर पहुंचे और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह है। जनसेवा में लापरवाही, अनुशासनहीनता या संवेदनहीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

रिवर्स पलायन को नई गति देगा उत्तराखंड मॉडल, राज्यभर में होंगी प्रवासी पंचायतें : मुख्यमंत्री धामी

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए राज्यभर में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा, ताकि देश-विदेश में कार्यरत प्रवासियों को उत्तराखंड से जोड़ा जा सके और उन्हें राज्य में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जा सके। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखंड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि पलायन लंबे समय से राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, लेकिन बीते चार-पांच वर्षों में सरकार ने इस दिशा में ठोस और परिणामोन्मुखी प्रयास किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके अंतर्गत ऋण पर अनुदान की सुविधा भी दी जा रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और लोगों का अपने गांवों की ओर लौटने का विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासी पंचायतों में प्रवासियों को रिवर्स पलायन से जुड़ी सरकारी पहलों की जानकारी देने के साथ-साथ उनके सुझाव भी प्राप्त किए जाएं। उन्होंने आयोग के सदस्यों से अन्य राज्यों में जाकर रिवर्स पलायन के सफल मॉडलों का अध्ययन करने और नवाचारों को उत्तराखंड में लागू करने पर भी बल दिया।

बैठक में वेडिंग डेस्टिनेशन विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रियुगीनारायण की तर्ज पर राज्य के 25 नए स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्थलों पर सड़क, बिजली, पानी, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लघु उद्योगों के संवर्धन को भी पर्वतीय विकास की रीढ़ बताया गया।

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी ने जानकारी दी कि रिवर्स पलायन की दिशा में उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक लगभग 6282 लोग अपने गांवों में वापस लौट चुके हैं, जिनमें देश और विदेश से लौटे नागरिक शामिल हैं। अधिकांश लोग पर्यटन और लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, धीराज गर्ब्याल, श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, अपर सचिव अनुराधा पाल, मेहरबान सिंह बिष्ट, चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, संतोष बडोनी, सुरेश जोशी सहित आयोग के सदस्य अनिल सिंह शाही, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, राम प्रकाश पैन्यूली और रंजना रावत उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के विकास की कसौटी पर चम्पावत ने मारी बाजी

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी और परिणाम आधारित मूल्यांकन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। राज्य में पहली बार सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अंतर्गत चिन्हित संकेतकों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का आकलन करते हुए मासिक रैंकिंग प्रणाली लागू की गई है। इस अभिनव व्यवस्था की पहली रैंकिंग में जनपद चम्पावत ने 96 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पूर्व में ही यह निर्देश दिए थे कि विकास योजनाओं की समीक्षा केवल कागजी नहीं, बल्कि एसडीजी संकेतकों की ठोस कसौटी पर की जाए, जिससे जिलों के वास्तविक प्रदर्शन का आंकलन संभव हो सके। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (सीपीपीजीजी) द्वारा एसडीजी की अवधारणा के अनुरूप जिलावार मासिक अनुश्रवण और रैंकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

11 एसडीजी और 39 संकेतकों पर आधारित मूल्यांकन

सीपीपीजीजी द्वारा अप्रैल से अक्टूबर माह तक 11 सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े कुल 39 प्रमुख संकेतकों का विस्तृत डाटा संकलित किया गया। समसामयिक लक्ष्यों और उपलब्धियों के आधार पर पहली बार जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसने राज्य के प्रशासनिक और विकास तंत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है।

इस रैंकिंग में चम्पावत ने 96 अंक के साथ पहला स्थान, बागेश्वर ने 94 अंक के साथ दूसरा स्थान जबकि नैनीताल ने 92 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है।

सीपीपीजीजी के विशेष कार्याधिकारी अमित पुनेठा ने बताया कि यह रैंकिंग न केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि पिछड़े जिलों के लिए भी एक स्पष्ट मार्गदर्शन सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि शेष वित्तीय वर्ष में सभी जिलों से अपेक्षा की गई है कि वे एसडीजी के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से हासिल करें। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में और भी नए संकेतकों को रैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

एसडीजी को लेकर उत्तराखंड की राष्ट्रीय पहचान

वर्ष 2030 तक गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अभाव से मुक्त विश्व के लक्ष्य को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। इन लक्ष्यों के चार प्रमुख आयाम–

सामाजिक समानता, समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज–को उत्तराखंड सरकार ने अपनी विकास नीति का केंद्र बिंदु बनाया है।

इन निरंतर और ठोस प्रयासों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे राज्य ने सतत विकास के क्षेत्र में अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई है।

उत्तराखंड में चिन्हित प्रमुख एसडीजी लक्ष्य

राज्य में जिन 11 सतत विकास लक्ष्यों पर विशेष फोकस किया गया है, उनमें शामिल हैं– गरीबी उन्मूलन, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, संवहनीय स्वच्छ ऊर्जा, उत्तम कार्य एवं आर्थिक उन्नति, उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना, असमानता में कमी, संवहनीय शहर एवं समुदाय, भूमि पर जीवन का संरक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए योजनाओं के बेहतर निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ठोस एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इससे न केवल आमजन के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि राज्य के समग्र और संतुलित विकास की परिकल्पना भी साकार होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले चम्पावत जिले सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी जिलों को बधाई दी और सभी जिलाधिकारियों व विभागों से आह्वान किया कि जिन लक्ष्यों और संकेतकों में सुधार की आवश्यकता है, उन पर विशेष ध्यान देते हुए निरंतर बेहतर प्रदर्शन की दिशा में कार्य करें।

जिला पूर्ति अधिकारी पर गिरी गाज, डीएम ने वेतन रोकने के दिए आदेश

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहना जिला पूर्ति अधिकारी को भारी पड़ गया। इस गंभीर अनुशासनहीनता को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारी का वेतन तत्काल प्रभाव से रोके जाने के आदेश दिए हैं तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को प्रेषित की है। जानकारी के

अनुसार, मुख्यमंत्री के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु 19 दिसंबर 2025 को जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक आहूत की गई थी। बैठक में सभी संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई थी, किंतु जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा बिना पूर्व अनुमति बैठक में अनुपस्थित रहकर शासकीय निर्देशों की अवहेलना की गई। बैठक के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी से कई बार दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, जिस पर उनके द्वारा अलग-अलग कारण बताए गए। इसके बावजूद स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बैठक में उपस्थित न होना और समीक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना, उनके शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। इसके चलते खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समुचित समीक्षा और निर्णय प्रभावित हुए।जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने इस कृत्य को मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च स्तर के कार्यक्रम से जुड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी के प्रति गंभीर अनुशासनहीनता करार देते हुए इसे कर्मचारी आचरण नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन बताया। उन्होंने प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल वेतन रोकने के आदेश जारी किए। साथ ही जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी अधिकारी द्वारा आदेशों की अवहेलना, लापरवाही अथवा बहानेबाजी को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री एवं शासन स्तर के कार्यक्रमों में पूर्ण गंभीरता, अनुशासन, उत्तरदायित्व और समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में आयोजित शिविर का ग्रामीणों को मिला लाभ

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़।

'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्ड पिथौरागढ़ की न्याय पंचायत सटगल के पंचायतघर मलान में बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटगांई द्वारा की गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना तथा स्थानीय स्तर पर प्राप्त जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से आम जनमानस को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही आवेदन प्राप्त कर पंजीकरण किया गया तथा अनेक मामलों में पात्र लाभार्थियों को तत्काल लाभ प्रदान किया गया।

चिकित्सा विभाग द्वारा 50 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श किया गया, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 47 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। विद्युत विभाग ने 5 प्रकरणों का निस्तारण किया, जबकि कौशल विकास विभाग ने 13 युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी जानकारी दी। पशुपालन विभाग ने 35, समाज कल्याण विभाग ने 31 और डेयरी विकास विभाग ने 31 लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा। ग्राम्य विकास विभाग ने 25, उद्योग विभाग ने 26 और उद्यान विभाग ने 23 लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया।

विभागों ने दी योजनाओं की जानकारी

एसबीआई, आरसेटी एवं लीड बैंक ने 45 व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता, ऋण एवं स्वरोजगार संबंधी जानकारी और लाभ प्रदान किए। मत्स्य विभाग ने 19, पेयजल विभाग ने 6, सैनिक कल्याण विभाग ने 26 और राजस्व विभाग ने 23 प्रकरणों का निस्तारण किया। आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी विभाग ने 180 नागरिकों को उपचार, परामर्श और औषधियां प्रदान कीं। वन विभाग ने 52 लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया और 2 पात्र लाभार्थियों को 15,000 रुपये वितरित किए, जिससे ग्रामीणों में सरकार की योजनाओं के प्रति विश्वास और उत्साह बढ़ा।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

शिविर के दौरान जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम हैं, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।

700 से अधिक ने लिया भाग

शिविर में लगभग 700 से अधिक स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों ने भाग लिया और कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताते हुए जिला प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास आशीष पुनेठा, डीडीओ रमा गोस्वामी, सहायक निदेशक मत्स्य रमेश चलाल, जिला क्रीड़ाधिकारी अनुप बिष्ट, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत, खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की वार्ता, हरसंभव सहयोग का मिला आश्वासन

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से दूरभाष पर संवाद कर उत्तराखंड में बढ़ रही मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है और वन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी व ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, हिंसक वन्यजीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष राज्य के लिए एक संवेदनशील विषय है, जिसमें जन-सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने इस दिशा में केंद्र सरकार से अतिरिक्त संसाधन, तकनीकी सहयोग और विशेष सहायता का अनुरोध किया, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और स्थायी समाधान सुनिश्चित किए जा सकें।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन, आधुनिक तकनीक के उपयोग और त्वरित राहत व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर सतत और प्रभावी रणनीति के साथ कार्य कर रही है।

बुजुर्ग महिला से मारपीट व तोड़फोड़, चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुरणपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और जमकर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित प्रवीण पुत्र तासीन निवासी ग्राम पुरणपुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते गुरुवार को उसकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए साजिद पुत्र रसीद व उसकी पत्नी सालदी निवासी ग्राम बौंगला बहादराबाद, फिरोज पत्नी रियासत निवासी ग्राम गुम्मावाला कलियर तथा भूरी पत्नी छेटा निवासी रुड़की सहित अन्य लोग उसके घर में घुस आए।

आरोप है कि सभी ने मिलकर उसकी 62 वर्षीय माता फातमा उमर के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने मारपीट के बाद घर में जमकर तोड़फोड़ की। घर में खड़ी मोटरसाइकिल, घास काटने की मशीन, टीन शेड, बाथरूम और गौशाला को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले के दौरान गौशाला में बंधी गाय को भी चोटें आने की बात सामने आई है। जब पीड़ित और उसके भाई की पत्नी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का मार्ग दिखाया: प्रधानमंत्री

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के साथ शुक्रवार को परंपरागत चिकित्सा पर आयोजित दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) के वैश्विक सम्मेलन का समापन हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में तीन दिनों तक चले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर से आए पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने गहन और सार्थक विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए डब्लयूएचओ, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और सम्मेलन में शामिल सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में पहले वैश्विक सम्मेलन के दौरान दुनिया ने भारत पर भरोसा जताते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी।

श्री मोदी ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का मार्ग दिखाया है। उन्होंने बताया कि भारत के प्रयासों और 175 से अधिक देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। आज योग दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच चुका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योग के प्रचार-प्रसार में योगदान देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किये।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि आज दिल्ली में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व (साउथ-ईस्ट) क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने इसे भारत की ओर से दुनिया को दिया गया एक विनम्र उपहार बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय शोध, नियम निर्धारण और क्षमता निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

श्री मोदी ने आयुर्वेद पर बात करते हुए कहा कि इसमें संतुलन को ही स्वास्थ्य माना गया है। उन्होंने कहा कि आज 'संतुलन बहाल करना' (रिस्टोरिंग बैलेंस) आज वैश्विक आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवनशैली, कम शारीरिक श्रम और आधुनिक सुविधाओं के कारण मानव शरीर के सामने नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ऐसे में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा की सुरक्षा और प्रमाणिकता के मुद्दे पर चर्चा करते हुये अश्वगंधा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि औषधि सदियों से भारत की पारंपरिक चिकित्सा का हिस्सा रही है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान इसकी वैश्विक मांग बढ़ी। उन्होंने कहा कि भारत अब शोध और साक्ष्य आधारित प्रमाणों के माध्यम से अश्वगंधा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। इस अवसर पर अश्वगंधा पर डाक टिकट भी जारी किया गया।

सम्मेलन में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मेल, डिजिटल तकनीक, एआई टूल्स और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। साथ ही दिल्ली डिक्लेरेशन को सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।

श्री मोदी ने सम्मेलन के समापन के साथ यह संदेश दिया गया कि पारंपरिक चिकित्सा अब लोकल से ग्लोबल (स्थानीय से वैश्विक) की दिशा में आगे बढ़ रही है और भारत इस वैश्विक प्रयास में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नयी दिल्ली। अठारहवीं लोकसभा के छठे सत्र में सदन की उत्पादकता 111 प्रतिशत रही और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों को सूचित करते हुए कहा 'अब हम 18वीं लोकसभा के छठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गये हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सदन की उत्पादकता लगभग 111 प्रतिशत रही।

इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों ने देर रात तक सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसके बाद अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी ।

एचआरडीए ने 15 बीघा की अवैध कॉलोनी पर चलाया बुलडोजर, भूमाफियाओं में हड़कंप

पथ प्रवाह, रुड़की/मंगलौर

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मंगलौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर न्यू एरा के बगल में स्थित भूमि पर विकसित की जा रही लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल की अनाधिकृत कॉलोनी को प्राधिकरण की रुड़की शाखा कार्यालय की टीम द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर विपक्षी देवराज एवं अंजार द्वारा बिना वैधानिक स्वीकृति एवं प्राधिकरण की अनुमति के प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मामले का संज्ञान लेते हुए एचआरडीए ने नियमानुसार कार्रवाई की गई। पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अवैध गतिविधियां जारी रहने पर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की।

ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क, प्लॉटिंग, बाउंड्री व अन्य अवैध संरचनाओं को मशीनों की सहायता से ध्वस्त किया। कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई।

प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों से न केवल नियोजित विकास बाधित होता है, बल्कि आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। एचआरडीए क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए गए किसी भी निर्माण या कॉलोनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने आम जनता से अपील की है कि भूमि क्रय करने से पूर्व संबंधित प्राधिकरण से मानचित्र एवं कॉलोनी की स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके। प्राधिकरण ने यह भी दोहराया कि नियोजित विकास और कानून का पालन सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

एक नजर

ढाबे की आड़ में शराब बेचने वाले ढाबा संचालक गिरफ्तार

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़। थाना जाजरदेवल से पुलिस ने भौड़ी से सुवालेख रोड पर स्थित एक भोजनालय की आड़ में लोगों को अवैध रूप से शराब परोसने वाले ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मान सिंह रावत है, थाना जाजरदेवल में उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना थल क्षेत्रान्तर्गत मुवानी बाजार में नवीन खनका निवासी सिरौली द्वारा सरेआम गाली-गलौच करते हुए उत्पात मचाया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सूचना पर थानाध्यक्ष थल प्रकाश पाण्डेय के नेतृत्व में अपर उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा मय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँचे। पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, परन्तु वह नहीं माना तथा और अधिक उग्र हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तथा किसी भी अप्रिय घटना की सम्भावना को रोकने हेतु पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया। इसके अतिरिक्त, जनपद पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन एवं मिशन मर्यादा अभियान के अंतर्गत कुल 94 व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

ज्वालापुर से 14 वर्षीय किशोरी लापता, गुमशुदगी दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। ज्वालापुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में ज्वालापुर के मोहल्ला कड़छ निवासी सोनू कुमार ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय भतीजी 17 दिसंबर को दोपहर के समय किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। शाम छह बजे तक जब किशोरी घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की। परिजनों ने पहले आसपास के इलाकों में, फिर रिश्तेदारी और जान-पहचान में किशोरी की तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना ज्वालापुर थाना पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। संभावित स्थानों पर छानबीन की जा रही है तथा जल्द ही किशोरी का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शाह ने समुद्री पोत और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए विशेष संस्था के गठन पर किया विचार विमर्श

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में समुद्री पोतों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर एक विशेष संस्था, ब्यूरो ऑफ़ पोर्ट सिक्योरिटी (बीओपीएस) के गठन पर शुक्रवार को विशेष बैठक में गहन विचार विमर्श किया। बैठक में बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री भी शामिल हुए। श्री शाह ने देश भर में मजबूत बंदरगाह सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की जरूरत बताते हुए निर्देश दिया कि सुरक्षा उपायों को कमियों, व्यापार क्षमता, स्थान और अन्य संबंधित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ब्यूरो ऑफ़ पोर्ट सिक्योरिटी का गठन नए मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जाएगा। ब्यूरो का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे और यह बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। यह समुद्री पोतों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित नियामक और निगरानी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। यह नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर बनाया जा रहा है।

कैरियर काउंसलिंग से संवर रहा बालिकाओं का भविष्य

पथ प्रवाह, पौड़ी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से विकासखंड कल्जीखाल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नन्दाखाल में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विभिन्न शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्रदान कर उनके भविष्य निर्माण हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान दिवाई अनुसूया देवी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गयी। बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्जीखाल द्वारा छात्र-छात्राओं को कैरियर काउंसिलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयीं।

कार्यक्रम के दौरान वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासिका द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिला हेल्पलाइन 181 के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गयी। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं को स्कूल बैग वितरित किए गए, जबकि विद्यालय में उपस्थित छात्रों को पेन एवं नोटबुक भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्जीखाल सुषमा रावत, कनिष्ठ सहायक महाराज सिंह रावत, गोपाल कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकत्री अरुणा, अंजू, सुनीता, पूर्णिमा, रीता सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन सुपरवाइजर सुनीता तोपवाल द्वारा किया गया।

न्याय तक सुलभ पहुंच की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल

पथ प्रवाह, पौड़ी। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के आदेशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम के निर्देशन में मेथोडिस्ट चर्च, पौड़ी में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी। इस दौरान महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के अधिकारों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। सभी वक्ताओं ने विधिक जागरुकता को सामाजिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए उपस्थित जनसमूह को आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के अल्पसंख्यक एवं वंचित वर्गों को विधिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें न्याय तक सरल, सुलभ एवं प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करना रहा।कार्यक्रम में पादरी हरीश कुमार, डिप्टी लीगल डिफेंस काउंसिल महेश बलूनी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार सहित अधिकार मित्र मनोज पाल, यशोदा, अमीषा एवं स्नेहा की गरिमामयी उपस्थिति रही।

बाराकोट लिंक रोड पर 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, योगी सेना ने बचाई दो जिंदगी

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़।

बाराकोट ब्लॉक क्षेत्रांतर्गत एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बाराकोट से तल्ला बापरु की ओर जा रही ऑल्टो कार (संख्या च 03 ङ्क 2143) पिथौरागढ़ लिंक रोड पर कैलाड़ी विद्युत पावर हाउस के समीप मोड़ पर अचानक अनियंत्रित हो गई और लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक अमित शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा एवं विक्रम सिंह पुत्र कुंवर सिंह, दोनों निवासी तल्ला बापरु, गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी 'योगी' के नेतृत्व में योगी सेना के युवा तुरंत मौके पर पहुंचे। गहरी खाई, अंधेरा और दुर्गम हालात के बावजूद टीम ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाराकोट चौकी को सूचना दी गई। घायलों को पुलिस वाहन से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। रेस्क्यू अभियान में योगी सेना के विजय नाथ, सूरज बिष्ट, सोनू चौधरी, ललित मोहन, राहुल जोशी, शुभम बिष्ट, हिमांशु नाथ, हिमांशु जोशी, सौरभ नाथ, धीरज सिंह सहित कई युवाओं ने सराहनीय योगदान दिया।

आकांक्षी कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तराखंड को मिली राष्ट्रीय पहचान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वश्रेष्ठ जिलों व विकासखंडों को किया सम्मानित, 'Uttarakhand at 25' पुस्तक का विमोचन

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्य सेवक सदन, देहरादून में आयोजित सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी जनपद कार्यक्रम एवं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों और विकासखंडों को प्रशस्ति पत्र एवं पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'Uttarakhand at 25: A Himalayan State With Infinite Possibilities' पुस्तक का विमोचन भी किया।

नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की शत-प्रतिशत पूर्ति एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जनपदों को पुरस्कृत किया गया। वहीं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने पर गदरपुर, मोरी और स्याल्दे विकासखंडों को सम्मान प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, आधारभूत ढांचा, सामाजिक विकास और वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। उन्होंने इसे राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जनपदों की रैंकिंग में हरिद्वार जनपद ने वर्ष 2022 में देश में

प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि गदरपुर, मोरी और स्याल्दे विकासखंडों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समग्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के साथ निरंतर जनकल्याण और विकास कार्यों को गति दे रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ?3.56 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए, जिनमें से ?1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को सशक्त बनाने के लिए एक जनपद, दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से राज्य के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स में उत्तराखंड का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में रहा, जबकि बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया गया है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को श्रेणी-सी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जो पारदर्शी और सक्षम प्रशासन का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का सिंगल विंडो सिस्टम टॉप अचीवर्स श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन और बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त किया है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में जाखोल, हर्षिल, गुंजी और सूपी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया।

उन्होंने कहा कि सही नीयत, नेक इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक सविता कपूर, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अदांकी, डायरेक्टर डॉ. मनोज पंत सहित अनेक अधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों की मुलाकातें जारी

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कैंप कार्यालय में आज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्या, विधायक उमेश शर्मा काऊ, किशोर उपाध्याय, डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, रुड़की मेयर अनिता अग्रवाल, कोटद्वार मेयर शैलेन्द्र रावत और भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की यह मुलाकात राज्य में चल रही विकास योजनाओं, पार्टी गतिविधियों और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद और चर्चा पर रही। अधिकारियों और विधायकों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आगामी कार्यक्रमों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। भेंट के दौरान उपस्थित सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को अपनी क्षेत्रीय गतिविधियों और जनता से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी तथा उनके मार्गदर्शन और सहयोग को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों की

मुलाकातों का यह सिलसिला लगातार जारी है, जो राज्य प्रशासन और विकास के लिए सहकारिता और समन्वय की भावना को मजबूत कर रहा है।

आईआईटी रुड़की में 'डिज़ाइन फॉर भारत-यूथ इनोवेशन चैलेंज' प्रदर्शनी का आयोजन

पथ प्रवाह, देहरादून

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के अंतर्गत आईआईटी रुड़की में 'डिज़ाइन फॉर भारत-यूथ इनोवेशन चैलेंज' प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित डिज़ाइन प्रतियोगिता 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को विकसित भारत ञ्च2047 के विजन के अनुरूप नवाचारी और प्रभावी डिज़ाइन समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस पहल का शुभारंभ युवा कार्य मंत्रालय एवं खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।

यह प्रतियोगिता भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियों के समाधान

हेतु डिज़ाइन-आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, जो सामाजिक प्रभाव और नवाचार को बढ़ावा देती है। चार चरणों में आयोजित इस प्रतियोगिता का समापन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं पुरस्कार समारोह के साथ किया जाएगा। इसी क्रम में, डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर, आईआईटी रुड़की द्वारा 16 दिसंबर 2025 को टिंकरिंग लैब, आईआईटी रुड़की में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से अनेक टीमों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया, जिनमें से चयनित टीमों को अपने नवोन्मेषी डिज़ाइन और रचनात्मक समाधानों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रदर्शनी के दौरान शीर्ष तीन टीमों का चयन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। कार्यक्रम का सफल समन्वय प्रोफेसर इंदरदीप सिंह, अधिष्ठाता (अवसंरचना) एवं समन्वयक, डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर, आईआईटी रुड़की द्वारा किया गया, जिन्हें इस प्रतियोगिता के लिए संस्थान का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

इस अवसर पर प्रोफेसर नवीन कुमार नवानी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य), तथा प्रोफेसर विवेक कुमार मलिक, अधिष्ठाता (प्रायोजित अनुसंधान एवं औद्योगिक परामर्श), आईआईटी रुड़की ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रोफेसर वरुण शर्मा, समन्वयक टिंकरिंग लैब; प्रोफेसर सोनल अत्रेय एवं प्रोफेसर विभूति रंजन भट्टाचार्य, डिज़ाइन विभाग; डॉ. अजय डी. जैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एसएमएयू हरिद्वार; सुमित्रा पांडे, इंडस्ट्रियल रिसर्च कंसल्टेंट; तथा डॉ. नील मणि, निदेशक, सीएआई एवं आर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com